GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 34
TO BE ANSWERED ON 06TH FEBRUARY, 2025

TELECOM CONNECTIVITY IN PVTG HABITATIONS, RURAL, REMOTE AND HILLY AREAS OF THE COUNTRY

34 # SHRI ADITYA PRASAD:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government is running any special scheme for installation of mobile towers to promote telecom connectivity in rural, remote and hilly areas of the country including Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) habitations;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any special project has been identified for strengthening mobile connectivity in PVTG habitations and rural areas in Jharkhand and in other States; and

(d) if so, the number of mobile towers that have been installed and proposed to be installed under it?

ANSWER

MINISTER OF COMMUNICATIONS AND DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION
(SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA IN RESPECT OF PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 34 FOR 06TH FEBRUARY, 2025 REGARDING "TELECOM CONNECTIVITY IN PVTG HABITATIONS, RURAL, REMOTE AND HILLY AREAS OF THE COUNTRY."

(a) to (d): Digital Bharat Nidhi (DBN) funds following specific schemes to provide mobile connectivity to the uncovered villages of rural, remote, hilly & Left-Wing Extremism (LWE) affected areas of the country.:

S.N.	Specific Scheme(s)
1	4G Saturation Scheme
2	7287 uncovered villages of Aspirational Districts
3	Left Wing Extremism Phase-II
4	Left Wing Extremism Phase-I Upgradation
5	Uncovered Villages of Arunachal Pradesh and 2 Districts of Assam
6	Uncovered Villages of Meghalaya and National Highway (NH)
7	502 uncovered villages of Aspirational Districts
8	354 Uncovered Village Scheme
9	Lakshadweep Islands
10	Uncovered villages and NH of Andaman & Nicobar Islands
As per list received from Ministry of Tribal Affairs (MoTA) to provide Mobile services to PVTG habitations under PRADHAN MANTRI JANJATI ADIVASI NYAYA MAHA ABHIYAN (PM JANMAN) under DBN funded 4G mobile projects, as on 31.12.24 the details are as **Annexed.**	

Annexure

Annexure refer to in part (a) to (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. 34 for answer on 06-02-2025

S. No	State	Towers planned	Habitations planned for Coverage	Towers installed	Habitations covered
1	Andhra Pradesh	742	1300	341	620
2	Chhattisgarh	103	150	19	28
3	Gujarat	26	41	11	18
4	Jharkhand	8	12	0	0
5	Karnataka	17	18	5	6
6	Kerala	27	41	10	19
7	Madhya Pradesh	138	158	16	20
8	Maharashtra	213	271	67	100
9	Odisha	331	426	31	61
10	Rajasthan	3	3	2	2
11	Tamil Nadu	28	53	3	4
12	Telangana	64	77	11	12
13	Tripura	12	39	3	11
14	Uttar Pradesh	2	3	0	0
15	West Bengal	2	3	0	0
Total		**1,716**	**2,595**	**519**	**901**

****

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *34
उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2025

देश के पीवीटीजी बस्तियों, ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क स्थापित करने की योजना

***34. श्री आदित्य प्रसादः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों सहित देश के ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु कोई विशेष योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड और अन्य राज्यों में पीवीटीजी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क को मजबूत करने के लिए किसी विशेष परियोजना की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत लगाए गए और लगाए जाने वाले मोबाइल टावरों की संख्या कितनी है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“देश के पीवीटीजी बस्तियों, ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क स्थापित करने की योजना” के संबंध में दिनांक 06 फरवरी, 2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) से (घ) के संबंध में विवरण

(क) से (घ): डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) देश के ग्रामीण, दूरदराज, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट योजनाओं को वित्तपोषित करती है:

क्र.सं.	विशिष्ट योजना(योजनाएँ)
1	4जी सैचुरेशन स्कीम
2	आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7287 गांव
3	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-II
4	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण-I उन्नयन
5	अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों के सेवा से वंचित गांव
6	मेघालय के सेवा से वंचित गांव और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)
7	आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांव
8	सेवा से वंचित 354 गांव स्कीम
9	लक्षद्वीप द्वीपसमूह
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सेवा से वंचित गांव और राष्ट्रीय राजमार्ग
डीबीएन द्वारा वित्तपोषित 4जी मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत पीवीटीजी बस्तियों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) से प्राप्त सूची के अनुसार, दिनांक 31.12.24 तक का ब्यौरा संलग्न है।	

*****

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 06-02-2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य**	**नियोजित टावर**	**कवरेज के लिए नियोजित बस्तियाँ**	**संस्थापित टावर**	**कवर की गई बस्तियाँ**
1	आंध्र प्रदेश	742	1300	341	620
2	छत्तीसगढ	103	150	19	28
3	गुजरात	26	41	11	18
4	झारखंड	8	12	0	0
5	कर्नाटक	17	18	5	6
6	केरल	27	41	10	19
7	मध्य प्रदेश	138	158	16	20
8	महाराष्ट्र	213	271	67	100
9	ओडिशा	331	426	31	61
10	राजस्थान	3	3	2	2
11	तमिलनाडु	28	53	3	4
12	तेलंगाना	64	77	11	12
13	त्रिपुरा	12	39	3	11
14	उत्तर प्रदेश	2	3	0	0
15	पश्चिम बंगाल	2	3	0	0
कुल		**1,716**	**2,595**	**519**	**901**

***

श्री आदित्य प्रसादः माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि झारखंड में अब तक स्वीकृत 8 मोबाइल टॉवरों में से एक भी टॉवर स्थापित नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हैं? नियोजित टॉवरों में कार्य की शुरुआत कब होगी? क्या इन सभी टॉवरों की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष रखा है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देश में पहली बार प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई है, जिसने समस्त आदिवासी समाज के केवल गाँवों नहीं, बल्कि टप्परों के भी सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' के तहत इन 25 हजार गाँवों एवं टप्परों के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, वहाँ केवल दूरसंचार की सुविधा नहीं, उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटेशन, पेयजल की समस्या का निवारण, संपूर्ण समस्याओं का holistic solution के लिए केबिनेट ने आदिवासी समाज के लिए 24 हजार करोड़ रुपए की योजना नवंबर, 2023 में पारित की। उसी के अंतर्गत हमारे सहभागी आदिवासी मंत्रालय ने हमें जुलाई, 2024 में गाँवों की लिस्ट, जहाँ दूरसंचार टॉवर की जरूरत है, एक सूचना भेजी, मतलब अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। उसका सर्वे दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा किया गया। सर्वे के अंतर्गत हम लोगों ने 2,590 गाँवों को चिन्हित किया, जहाँ हम 1,716 टॉवर्स लगाने जा रहे हैं। यह 15 राज्यों में है और तीन स्कीम्स के अंतर्गत है। जैसा मैंने कहा कि इसमें केवल गाँव शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें मजरे, टोले भी शामिल हैं और कई गाँवों, मजरे एवं टोलों में अभी भी lat-long की कठिनाई हो रही है, Unique Census Code नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिपोर्ट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन 2,590 गाँवों में से 901 गाँवों में हमारे टॉवर्स लग चुके हैं। 1,716 टॉवर्स में से 519 टॉवर्स लग चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने की अवधि में, जुलाई, 2024 से आज तक सर्वे हो चुका, गाँव रेखांकित हो चुके और टॉवर्स भी लग चुके। हमने 35 प्रतिशत काम रिकॉर्ड टाइम में किया है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि तीसरा टर्म, मतलब तीन गुना ज्यादा मेहनत, तीन गुना ज्यादा शक्ति और तीन गुना ज्यादा रिजल्ट और यही दूरसंचार मंत्रालय ने करने की कोशिश की है।

सर, जहाँ तक झारखंड की बात की गई, वहाँ हम लोगों ने केवल 8 टॉवर्स नहीं, बल्कि समूचे राज्य के लिए 2,471 गाँवों में 1,987 टॉवर्स रेखांकित किए हैं। हमारे जो बचे हुए मजरे, टोले हैं, उनके लिए ये 8 टॉवर्स रेखांकित किए गए हैं। इसमें तीन कठिनाइयाँ हैं। पहला - लैंड की कठिनाई है। झारखंड सरकार टॉवर लगाने के लिए जमीन देने में थोड़ी लेट-लतीफी कर रही है। दूसरा - right of way की problem है और उसी के साथ कुछ लोकेशन्स inaccessible हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।

श्री आदित्य प्रसादः माननीय उपसभापति महोदय, चूंकि झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल से बात करने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि क्या इन क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, not only in Jharkhand, but also in all the Left Wing Extremism (LWE) affected areas, we have two schemes. The first scheme is of Rs.2,400 crore started in May, 2024 and the second scheme is of Rs.2,200 crore started in October, 2021. Both of them are supposed to be completed in the middle of 2025. This includes all the LWE affected areas, not only Jharkhand.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज़ और अफॉर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या यह उनके संज्ञान में है कि हाल ही में 3 जुलाई, 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज़ ने एक concerted तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों, जिनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, उन पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा? क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल कंपनीज़ द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए एक मौका दिया कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में प्रधान मंत्री जी की नेतृत्व में दूरसंचार के वातावरण में क्या बदलाव आया है,क्या क्रांति आई है। सर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे।

श्री जयराम रमेशः आप सीधा जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: जयराम जी, आप सीट पर बैठकर न बोलें। माननीय मंत्री जी, आप बोलें।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, जयराम जी को * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam*ji*, this is not going on record. ...(*Interruptions*) ...

---

* Not recorded.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त, रणदीप जी अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं।

श्री उपसभापतिः आप सवाल का जवाब दें।

श्री ज्योतिरादित्य एम .सिंधियाः सर, मैं बता रहा था कि पहले 90 करोड़ ग्राहक थे, आज दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल की सेवा में 116 करोड़ ग्राहक हैं। अगर हम internet penetration की बात करें, तो 2014 में 25 करोड़ ग्राहक थे, जो आज करीब 97.4 करोड़ हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं वहां आ रहा हूं, रणदीप जी।

सर, अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें, जिसकी कनेक्टिविटी 2 जीबीपीएस से ज्यादा होती है, 140 करोड़ के देश में उसके केवल 25 करोड़ ग्राहक थे, जो आज बढ़कर देश के अंदर 92 करोड़ हो चुके हैं। यह जरूर है कि जब ये नंबर्स बढ़ते हैं, तो दाम पर भी पूरी तरह से निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, जैसा रणदीप जी ने कहा।

मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि 2014 में मोबाइल पर एक मिनट की कॉल के लिए 50 पैसे लगते थे, जो आज 10 साल बाद 2025 में एक मिनट की कॉल के लिए तीन पैसे लिए जाते हैं। मतलब, कॉस्ट स्ट्रक्चर में 94% की गिरावट आई है। ...(**व्यवधान**)... मैं उनको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि 2014 में ब्रॉडबैंड की कॉस्ट 270 रुपये प्रति जीबी होती थी, जो आज 10 साल बाद, इस देश के अंदर प्रति जीबी कॉस्ट 9 रुपये, 70 पैसे है। इस प्रकार, इसमें 93% की गिरावट आई है। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में डेटा के आधार पर सबसे किफायती देश है। जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, मैं आपको सदैव स्पष्टता से जवाब देता हूं, इसलिए कहता हूँ कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में जरूर 10% की इंक्रीज़ हुई है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: वह क्यों हुई है? आज पूरे विश्व में भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में telecom companies के द्वारा fastest roll out of 5G हुआ है। 22 महीने में 98 per cent districts or 82 per cent population 5G की कवरेज हुई है। मतलब यह कि साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। अगर साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का निवेश हो, तो क्या निवेश करने वाले लोगों के लिए थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? अगर कॉल की कॉस्ट तीन पैसे से साढ़े तीन पैसे हो चुकी, तो ultimately return भी तो होना चाहिए। आज डेटा और वॉयस पर सबसे cheapest ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. *...(Interruptions)...*

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: सर, आज पूरे विश्व में भारत में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वॉयस और डेटा सबसे cheapest है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra - fourth supplementary.

DR. SASMIT PATRA: Hon. Deputy Chairman, Sir, my specific question to the hon. Minister has a brief preface and I will be quick. Odisha is home to the largest number of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) in India, and the answer also says that PVTG is, probably, a part of the habitation. So, out of the 426 habitations planned, 61 have been completed. My question is: How many of these habitations belong to the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) in Odisha? How many have been completed, and by when all of these would be completed? Thank you.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, Sasmit bhai has asked a very pertinent question and it goes back to the answer I gave in response to the first supplementary. The hon. Prime Minister has very clearly resolved that all the PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure and all physical infrastructure, and this is very much a part of that. I would like to inform that 2,595 habitations have been planned and 1,716 towers have been planned. Out of these, Odisha number today here is 331 towers. All these 331 towers in 426 habitations are PVTG habitations. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Odisha is 4,511 covering 6,064 habitations. But, of that, the subset is 331 towers, covering 426 habitations, all PVTG, and it is our commitment to do this as soon as possible. Yes, there are 'right of way' issues; there are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sumer Singh Solanki - fifth supplementary and the last one.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: उपसभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत में संचार क्रांति आई है। मैं मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां नेटवर्क की समस्या धीरे-धीरे कम हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क के लिए टॉवर लगाने का काम किया जा रहा है, साथ ही, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर संचार सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, यह मध्य प्रदेश के अंदर कब तक पूर्ण हो जाएगा?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए हम लोगों ने जो आवंटन किया है, उसमें कुल मिलाकर 2,202 गाँवों में 1,650 टॉवर्स लगाए जाएंगे, उनमें से वर्तमान में 981 गाँवों में 771 टॉवर्स ऑलरेडी लग चुके हैं और जहां तक हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां 138 टॉवर्स करीब 160 गाँवों में लगाने का निर्णय लिया

गया है और शीघ्र ही इसे complete किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जुलाई, 2024 में ही आदिवासी मंत्रालय से हमें इनकी पूरी लिस्ट मिली है। हमने सर्वे कर लिया है और कार्य भी प्रगित पर है। हम लोग इसे जल्द से जल्द रिकॉर्ड समय में खत्म करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No.35.